अशोका एक्सप्रेस

SNA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 17 ● नई दिल्ली ● 09 से 15 मई 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

तमिलनाडु में सियासी खींचतान जारी, वीसीके ने समर्थन देने के लिए मांगा उप-मुख्यमंत्री का पद

बार आपका इंतजार कर रहा है, महिला वकील की याचिका खारिज कर सीजेआई सूर्यकांत ने सुनाया दिलचस्प निजी किस्सा

नई दिल्ली ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को अदालत में एक दिलचस्प निजी अनुभव साझा करते हुए न्यायिक सेवा अभ्यर्थी को भविष्य के लिए प्रेरित किया। दरअसल, न्यायिक सेवा परीक्षा की अभ्यर्थी प्रेरणा गुप्ता अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अपना निजी अनुभव साझा कर माहौल को भावुक बना दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि जब वह कानून की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने भी न्यायिक सेवा के लिए आवेदन किया था। उस समय अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते थे। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में बदलाव के बाद हाई कोर्ट के जजों की राय निर्णायक हो गई थी। सीजेआई ने बताया कि उसी दौरान उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। इंटरव्यू पैनल में शामिल एक वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें पहले से जानते थे, क्योंकि वह उनके समक्ष दो महत्वपूर्ण मामलों में बहस कर चुके थे। सीजेआई ने बताया कि एक दिन उस न्यायाधीश ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर पूछा कि क्या वह न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं। उनके हां कहने पर न्यायाधीश ने तुरंत उन्हें बाहर जाने को कह दिया। सीजेआई ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा कि उनके सारे सपने टूट गए हैं और उनका करियर खत्म हो गया। हालांकि अगले दिन वही न्यायाधीश फिर मिले और उन्होंने सलाह दी कि अगर वह न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह वकालत जारी रखें क्योंकि बार उनका इंतजार कर रही है।

सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में शामिल न होने का फैसला किया और पूरी तरह वकालत पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अदालत में मौजूद याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनका वह फैसला गलत था। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थी को भविष्य में उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा देने और आगे बढ़ने की सलाह दी। याचिका खारिज होने के बावजूद प्रेरणा गुप्ता अदालत से मुस्कुराते हुए बाहर निकलीं।

गर्मी का इलाज, जेब में रखो प्याज, दिल्ली के Heat Action Plan पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के लू अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज़ रखो की लू कार्य योजना की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का यह तंज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस पुराने नुस्खे पर था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे गर्मी के चरम मौसम में अपनी जेब में प्याज रखते हैं ताकि गर्मी से राहत पा सकें । रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग के नारे के साथ देश की राजधानी के लिए एक हीट एक्शन प्लान की घोषणा की है। दरअसल, उनके भाजपा सहयोगी और मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज रखो के नारे के साथ हीट एक्शन प्लान शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना स्थित अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि आज के युग में हर कोई फोन रखता है, लेकिन वह प्याज रखते हैं, क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए अपनी जेब से एक प्याज निकाला, जिससे वहां मौजूद लोग खूब हंसे। सिंधिया ने कहा कि मैं अपनी कार में एसी नहीं चलाता, मैं बस अपनी जेब में एक प्याज रखता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री ने आगे कहा कि अपनी जेब में एक प्याज रखिए; 51 डिग्री की गर्मी में भी कुछ नहीं होगा।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी
के लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू अध्यक्ष
भाई देवेन्द्र यादव जी
के संघर्ष, सेवा और समर्पण के
2 वर्ष दमदार
पूर्ण होने पर
शुभकामनाएँ

भाई देवेन्द्र यादव
अध्यक्ष व पूर्व विधायक

निवेदक: किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी

विजय कुमार भारती
पत्रकार, महासचिव: किराड़ी जिला

रिपब्लिकन मज़दूर संगठन

राजनीति का रक्त चरित्र

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई लेकिन चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों में सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जिसमें सत्ता में बैठने वालों ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसा को हथियार बनाया। चुनाव आते हैं, जाते हैं। जय-पराजय भी चलती रहती है लेकिन मौत का खेल लोकतंत्र के लिए घातक ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई लेकिन खूनी सियासत ने पश्चिम बंगाल में सभी हदें पार कर दीं। पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह से लहूलुहान रही है। चुनाव आयोग द्वारा इस बार कड़े सुरक्षा प्रबंधों के चलते चुनावों के दौरान छिटपुट हिंसा की घटनाओं को छोड़कर कोई जनहानि नहीं हुई। इससे सभी ने राहत की सांस ली थी। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल कर ममता बनर्जी की 15 वर्ष पुरानी तृणमूल सरकार को उखाड़ फैंका। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी लेकिन चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया। बुधवार की रात भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने वाले शुभेन्दु अधिकारी के निजी सचिव चन्द्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की गई। उससे यह सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है कि क्या राज्य की सियासत का चरित्र बदलेगा या पूर्व की तरह ही चलता रहेगा। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में 2 भाजपा और 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और तोड़फोड़ और आगजनी का दौर जारी है। जीत में उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और जिस ढंग से अपने आप बुलडोजर चलाकर तृणमूल समर्थकों की दुकानों को ध्वस्त किया वह भी उतना ही निंदनीय है जितना की तृणमूल की गुंडागर्दी की निंदा की जाती है। शुभेन्दु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या के लिए यद्यपि भाजपा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को आरोपी करार दे रही है लेकिन फिलहाल निष्पक्ष जांच के बाद किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि क्या यह हत्या निजी रंजिश के चलते हुई है या इसके तार सियासत से जुड़े हुए हैं। इन हत्याओं ने भाजपा की जीत के जश्न को गुलाल की बजाय खून से रंग दिया है। अगर पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो यह एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां सियासी दुश्मनों को हराया नहीं जाता बल्कि खत्म कर दिया जाता है। बंगाल के गौरवशाली इतिहास और बौद्धिक संस्कृति को पहले 34 साल के कम्युनिस्ट शासन की सियासत ने धुंधला किया। गांव से लेकर कोलकाता के सत्ता के गलियारों तक पार्टी की सरकार थी और सरकार ही पार्टी। इसी कैडर कल्चर से राजनीतिक दुश्मनी ने जन्म लिया। कौन किसे वोट देगा यह लोग नहीं, पार्टी तय करती थी।

एक पूरी पीढ़ी तक शासन करने वाली वामपंथी पार्टियों ने राजनीतिक हिंसा की नींव डाल दी। तीन दशक से भी ज्यादा के कम्युनिस्ट शासन में 20 हजार से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं की गई थीं। कम्युनिस्टों ने हिंसा और गैर जिम्मेदार ट्रेड यूनियन वार की वकालत और नेतृत्व करके पूंजीवाद को बंगाल से बाहर निकाल दिया और राज्य को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। इसी खूनी राजनीति के बीच एक उम्मीद बनकर उभरीं ममता बनर्जी। लेफ्ट की हिंसक राजनीति को हराकर सत्ता में तो आईं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपना लिया। बंगाल की टीएमसी में कार्यकर्ता कितने थे पता नहीं, पर गुंडों की कोई कमी नहीं थी। 2018 का पंचायत चुनाव हो, 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा हो, या 2023 के पंचायत चुनाव के बाद का खून-खराबा, सब एक जैसा था। विरोधी पार्टियों के दफ्तरों में आग लगाना, लोगों के घरों में घुसकर टीएमसी को वोट देने की धमकी देना बंगाल में आम बात हो गई। गांवों में टीएमसी का विरोध करने वालों के पास दो ही रास्ते थे-या तो गांव छोड़ दो, या टीएमसी को वोट दो। टीएमसी का विरोध करने वालों को जहां-तहां पीटा गया, झूठे केसों में जेल में डाल दिया गया। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें खत्म कर दिया गया और उनके घर की महिलाओं पर अत्याचार किए गए। ममता के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे को भूल गई। ममता के राज में 300 से ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं, जबकि रेप के मामलों का तो कोई हिसाब ही नहीं। कई महिलाओं ने तो इज्जत के डर से पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा। उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि अगर वे शिकायत करने गईं तो सुरक्षित घर लौट पाएंगी। 2021 तक टीएमसी की खूनी राजनीति एक स्तर पर थी, लेकिन उसके बाद के हालात और भी भयानक हो गए। थोक में वोट पाने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाना और सिर्फ इसलिए हिंदुओं को निशाना बनाना क्योंकि उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, यह सब टीएमसी के गुंडों के जरिए चल रहा था। बंगाल के लोगों के सब्र का बांध टूटने में 15 साल लग गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में एक भी सीट न जीत पाने वाली बीजेपी, 2016 में 3 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी, आज 77 से 206 सीटें जीतने के स्तर पर आ गई है। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और न ही हिंसा को स्वीकार किया जा सकता है। भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा को समाप्त करना, आपराधिक तत्वों और गुंडा कल्चर को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती है।

हल्दीघाटी का अमर योद्धा

भारत के स्वर्णिम इतिहास में यदि अदम्य साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का कोई सर्वोच्च प्रतीक खोजा जाए, तो वह नाम है महाराणा प्रताप। यह नाम मात्र उच्चारण से ही मन में वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति का ज्वार उत्पन्न कर देता है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अडिग संकल्प के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ की वीरभूमि (वर्तमान राजस्थान) में हुआ। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे। उस समय मेवाड़ निरंतर संघर्षों से गुजर रहा था और चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। ऐसे कठिन समय में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। उनके सामने न केवल बाहरी आक्रमण का खतरा था, बल्कि आंतरिक चुनौतियाँ भी थीं। उनके राज्याभिषेक के समय उत्तराधिकार को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने एकमत होकर उन्हें ही योग्य शासक मानते हुए गद्दी सौंपी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने अनेक राजाओं को मित्रता और संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को भी संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उनके लिए स्वाभिमान सर्वोपरि था। वे जानते थे कि संधि का अर्थ पराधीनता स्वीकार करना है, जो उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध का वह ऐतिहासिक दिन आया, जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने-सामने हुई। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। मुगल सेना संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित सेना थी, जिसमें राजपूतों के साथ भील योद्धाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। युद्ध अत्यंत भीषण और रक्तरंजित था। महाराणा प्रताप ने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए शत्रु सेना को कड़ी चुनौती दी। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक विजय में परिवर्तित नहीं हुआ, किंतु प्रताप की वीरता और संघर्षशीलता ने उन्हें अमर बना दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की स्वामीभक्ति और बलिदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय उदाहरण माने जाते हैं। वनवास, संघर्ष और पुनः विजय हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में रहकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा की। अंततः अपने जीवनकाल में उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः स्वतंत्र करा लिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, धैर्य और दृढ़ संकल्प से विजय प्राप्त की जा सकती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्ध और पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है। उन्होंने कभी भी भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं दी।

जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के जरेरा टैंक के जीर्णोद्धार से किसानों को मिला पानी

-इंजेश सिंह

जनपद चित्रकूट के तहसील मानिकपुर के अंतर्गत आने वाला पाठा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण इलाका माना जाता है, जहाँ पथरीली भूमि, असमान स्थलाकृति तथा सीमित जल संसाधनों के कारण कृषि कार्य सदैव कठिन रहा है। इस क्षेत्र में स्थित जरेरा टैंक (तालाब), जिसका निर्माण कई वर्षों पूर्व स्थानीय किसानों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत के रूप में स्थापित हुआ था। लगभग 0.350 किलोमीटर लंबाई और 2.69 मिलियन क्यूबिक मीटर (डब्ड) जल भंडारण क्षमता वाला यह टैंक प्रारंभिक वर्षों में सिंचाई, पशुपालन तथा अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। समय के साथ यह टैंक क्षेत्रीय जल प्रबंधन का आधार बना था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसने इसकी उपयोगिता को लगभग समाप्त कर दिया। वर्षों के उपयोग और प्राकृतिक कारणों के चलते टैंक में भूमिगत सीपेज (ैममचंहम) की समस्या अत्यधिक बढ़ गई। टैंक वर्षा ऋतु में तो पूर्ण रूप से भर जाता था, परंतु चट्टानी संरचना में मौजूद सूक्ष्म एवं विस्तृत दरारों (त्वबा थ्पेनतमे) के कारण पानी धीरे-धीरे जमीन के भीतर रिसने लगता था। परिणामस्वरूप, वर्षा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद जल स्तर तेजी से गिरने लगता था और नवंबर माह से पहले ही टैंक लगभग खाली हो जाता था। इस स्थिति का सीधा प्रभाव क्षेत्र के किसानों पर पड़ता था, विशेष रूप से रबी फसल के समय, जब सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पानी की अनुपलब्धता के कारण किसान सीमित क्षेत्र में ही खेती कर पाते थे, जिससे उनकी आय प्रभावित होती थी और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती थी। इसके साथ ही, लगातार जल रिसाव के कारण आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर भी गिरता जा रहा था, जिससे पेयजल संकट भी गहराने लगा था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराया गया। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि टैंक के अपस्ट्रीम क्षेत्र में चट्टानों के भीतर कई स्थानों पर अवपके और पिनतमे मौजूद हैं, जो जल के रिसाव के मुख्य कारण हैं। पारंपरिक उपाय, जैसे मिट्टी भराई या सतही मरम्मत, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक वैज्ञानिक एवं दीर्घकालिक समाधान अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के तहत सीमेंटेशियस ग्राउटिंग (ब्मउमदजपजपवने ळतवनजपदह) अथवा कर्टेन ग्राउटिंग (ब्नतजंपद ळतवनजपदह) तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया गया, जो जलाशयों में सीपेज नियंत्रण के लिए एक प्रभावी और प्रमाणित तकनीक मानी जाती है। कार्य के अंतर्गत टैंक के अपस्ट्रीम में 0.100 किलोमीटर से 0.300 किलोमीटर के बीच लगभग 200 मीटर लंबाई में ग्राउटिंग कार्य किया गया। इस प्रक्रिया में सबसे पहले निर्धारित क्षेत्र में तीन पंक्तियों (त्वे) में ड्रिलिंग की गई, जिनके बीच की दूरी लगभग 3-3 मीटर रखी गई। प्रत्येक पंक्ति में 5-5 मीटर के अंतराल पर ड्रिल होल बनाए गए, जिनकी गहराई 4 मीटर तथा 7 मीटर (चट्टान के भीतर) तक रखी गई। इन होल्स को अल्टरनेट क्रम में तैयार किया गया, ताकि अधिकतम क्षेत्र को कवर किया जा सके और सभी संभावित दरारों तक सीमेंट स्लरी पहुँच सके। इसके बाद उच्च दबाव (च्तमेनतम) के साथ सीमेंट स्लरी को इन होल्स में डाला गया, जिससे यह स्लरी चट्टानों की दरारों और खाली स्थानों में फैलकर उन्हें पूरी तरह भर सके। ग्राउटिंग की यह प्रक्रिया अत्यंत तकनीकी और सावधानीपूर्ण थी, क्योंकि इसमें सही दबाव, उचित मिश्रण अनुपात तथा सटीक ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। यदि इन मानकों का सही पालन न किया जाए, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इस कार्य के दौरान कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आईं। विशेष रूप से, अपस्ट्रीम क्षेत्र में अत्यधिक कीचड़ (ैसनी) होने के कारण ड्रिलिंग मशीनों को स्थापित करने और संचालित करने में कठिनाई हो रही थी। कई स्थानों पर ड्रिल होल स्थिर नहीं रह पा रहे थे, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए पहले कार्य स्थल से कीचड़ हटाया गया और उसके स्थान पर मिट्टी डालकर एक मजबूत आधार तैयार किया गया। इसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से ड्रिलिंग और ग्राउटिंग कार्य को आगे बढ़ाया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस वैज्ञानिक एवं सुनियोजित हस्तक्षेप के परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहे। जून 2024 तक टैंक में सीपेज नियंत्रण का कार्य लगभग पूर्ण रूप से सफल हो गया। अब टैंक में संचित जल लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगा है और अनावश्यक जल रिसाव में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहाँ टैंक नवंबर से पहले ही खाली हो जाता था, वहीं अब इसमें वर्ष भर या लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहने लगा है। इससे टैंक की जल धारण क्षमता में स्थायित्व आया है और यह पुनः एक विश्वसनीय जल स्रोत के रूप में स्थापित हो गया है। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्षेत्र के किसानों को प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत निही चिरइया सहित आसपास के गांवों के कृषकों को अब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2024-25 में रबी फसल के दौरान कुल 1432 हेक्टेयर क्षेत्र में से 338 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की जा सकी, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। किसान अब अधिक क्षेत्र में खेती कर पा रहे हैं और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण और सामाजिक जीवन पर भी देखा गया है। टैंक में जल उपलब्धता बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर (ळतवनदकूंजमत स्मअमस) भी बढ़ा है, जिससे हैंडपंप और कुओं में पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है। क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है और सूखे की स्थिति में भी जल उपलब्धता बनी रहती है। पशु-पक्षियों, वन्य-जीवों के लिए भी यह टैंक एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बन गया है, जिससे जैव विविधता को भी लाभ मिला है। ग्रीष्म ऋतु में, जब जल संकट अपने चरम पर होता है, तब भी टैंक में जल उपलब्ध रहने से ग्रामीणों को राहत मिलती है। जरेरा टैंक का यह पुनरुद्धार केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह सतत जल प्रबंधन (ैनेजंपदंइसम ॅजमत डंदंहमउमदज) का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस परियोजना ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सही तकनीक, उचित योजना और प्रभावी क्रियान्वयन को एक साथ जोड़ा जाए, तो पुरानी और निष्क्रिय जल संरचनाओं को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। कर्टेन ग्राउटिंग जैसी तकनीक न केवल सीपेज को नियंत्रित करने में सक्षम है, बल्कि यह जलाशयों की आयु और उपयोगिता को भी बढ़ाती है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव अन्य समान जलाशयों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से, ऐसे क्षेत्र जहाँ चट्टानी संरचना के कारण जल रिसाव की समस्या होती है, वहाँ इस तकनीक को अपनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

यह मॉडल कम लागत में अधिक लाभ देने वाला है और इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है। जरेरा टैंक की यह सफलता की कहानी प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की किसान एवं गाँवों के नेतृत्व में जल संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिवर्तन ला रहे हैं। इस परियोजना ने न केवल एक जलाशय को पुनर्जीवित किया, बल्कि इससे जुड़े हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाया है। किसानों की बढ़ती आय, बेहतर कृषि उत्पादन, सुधरता हुआ पर्यावरण और स्थायी जल उपलब्धता-ये सभी इस पहल की सफलता के प्रमाण हैं। जरेरा टैंक आज एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है, जो यह सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा सार्थक परिणाम देता है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

चार दशकों से निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को समर्पित वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का भव्य सम्मान

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह)पत्रकारिता जगत में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार के आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी को उनकी चार दशकों से अधिक की उत्कृष्ट, निर्भीक एवं जनपक्षधर पत्रकारिता सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। अपने लंबे पत्रकारिता करियर में आशुतोष चतुर्वेदी ने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों – प्रभात खबर, अमर उजाला, माया, इंडिया टुडे, संडे ऑब्जर्वर, दैनिक जागरण और बीबीसी लंदन – में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

निभाई। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अहम असाइनमेंट्स को सफलतापूर्वक कवर किया। राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश यात्राओं की रिपोर्टिंग में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में भी उनका विशेष योगदान रहा। बीबीसी हिंदी वेबसाइट के लॉन्च में उनकी अहम भूमिका को पत्रकारिता जगत की बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर, मोमेंटो और स्मारिका भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि आशुतोष चतुर्वेदी ने अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में निष्पक्षता, साहस और मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया कई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में आशुतोष जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने में आशुतोष चतुर्वेदी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। समाज और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाकर उन्होंने पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को मजबूत किया।

हाईवे पर ट्रकों की मनमानी बनी मौत का रास्ता-विजय शंकर चतुर्वेदी ने नितिन गडकरी से की सख्त कार्रवाई की मांग

दिल्ली। (आकाश शक्य) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती अव्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रख्यात समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कड़े और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ट्रकों की मनमानी आवाजाही अब आम लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। भारी वाहन सभी लेनों में चलते हैं, ओवरटेक करते हैं और कई बार छोटे वाहनों को घंटों जाम और जोखिम भरी स्थिति में फंसा देते हैं।

विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि देश के एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इन सड़कों पर ट्रकों की अनुशासनहीनता के कारण आम वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहन चालकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक बनती जा रही है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग करते हुए कहा कि सभी

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ट्रकों के लिए अलग और निश्चित लेन निर्धारित की जाए। ड्डह्नकों को केवल निर्धारित लेन में ही चलने की अनुमति हो और इसका सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि भारी ट्रक बीच और फास्ट लेन तक में चलते हैं, जिससे छोटे वाहनों की गति रुक जाती है और दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

चतुर्वेदी ने यह ड्डह्यह्यश मांग की कि नियम तोड़ने वाले ट्रक चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पहली गलती पर भारी जुर्माना, दूसरी बार लाइसेंस निलंबन और लगातार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाए। इसके साथ ही ट्रक मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाए और बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों को जब्त करने की व्यवस्था लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि सख्त क्रियान्वयन से सुनिश्चित होती है। यदि सरकार ट्रकों की लेन व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाए और तकनीकी निगरानी बढ़ाए, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने हाईवे पर सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक चालान सिस्टम और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की।

विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि सड़क पर अनुशासन केवल सुविधा का नहीं बल्कि जीवन रक्षा का विषय है। हर दिन होने वाली दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसका एक प्रमुख कारण भारी वाहनों की लापरवाही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तुरंत नई नीति लागू की जाए, ताकि देश के हाईवे सुरक्षित, व्यवस्थित और भयमुक्त बन सकें।

अब ब्रांड के नाम से पहचाने जाएंगे नमो भारत के 21 स्टेशन, विज्ञापनों से होगी लाखों की कमाई

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर भी अब स्टेशनों के नाम ब्रांड के नाम पर रखे जाएंगे। एनसीआरटीसी ने 21 स्टेशनों के लिए सेमी-नेमिंग और को-ब्रांडिंग अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे कंपनियों को बड़ा प्रचार मिलेगा और एनसीआरटीसी को लाखों की कमाई होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत कॉरिडोर के 21 स्टेशनों के लिए सेमी-नेमिंग और को-ब्रांडिंग अधिकार देने के लिए निविदाएं जारी की हैं। इस योजना के तहत कंपनियां स्टेशन के नाम के साथ अपना ब्रांड जोड़ सकेंगी, जिससे स्टेशन की पहचान के साथ उनका नाम लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। ये पहल इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक 3 करोड़ से यादा यात्री सफर कर चुके हैं। ऐसे में कंपनियों को एक साथ लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा। निविदा के मुताबिक, लाइसेंस की अवधि शुरुआती तौर पर 10 साल होगी, जिसे आपसी सहमति से 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी ब्रांड लंबे समय तक स्टेशन से जुड़ा रह सकता है। इस योजना में कंपनियों को सिर्फ नाम जोड़ने का ही नहीं, बल्कि स्टेशन के हर हिस्से में ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। इसमें कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म, एंट्री-एग्जिट गेट, बाहरी पिलर (पियर्स) तक शामिल हैं। इससे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के साथ सड़क से गुजरने वाले लोगों तक भी ब्रांड की पहुंच बनेगी। ट्रेनों में होने वाली अनाउंसमेंट में भी को-ब्रांडेड स्टेशन का नाम लिया जाएगा। स्टेशनों के मैप पर ब्रांड का लोगो दिखेगा और कंपनियों को कियोस्क लगाने की सुविधा भी दी जाएगी। इससे कंपनियां सीधे ग्राहकों से जुड़ सकेंगी। जिन 21 स्टेशनों के लिए यह मौका दिया जा रहा है, उनमें सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, डौरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम शामिल हैं। एनसीआरटीसी का कहना है कि ये सभी स्टेशन घनी आबादी वाले इलाकों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों के पास हैं, जिससे ब्रांड को यादा एक्सपोजर मिलेगा। एनसीआरटीसी का मानना है कि इस पहल से जहां कंपनियों को बड़ा मार्केट मिलेगा, वहीं उसे भी अछी आय होगी, जिससे आगे के प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलेगी।

प्रख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. भीमसेन बंसल की आठवीं पुण्यतिथि पर चिकित्सा जगत और कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह)देश के प्रसिद्ध चिकित्सक, आर.जी. स्टोन हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं समाजसेवा के पर्याय माने जाने वाले स्वर्गीय डॉ. भीमसेन बंसल की आठवीं पुण्यतिथि पर चिकित्सा जगत, सामाजिक क्षेत्र और कांग्रेस परिवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके द्वारा समाज और चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें सच्चा मानवसेवी और जननायक बताया गया।

डॉ. भीमसेन बंसल ने अपने जीवनकाल में लाखों मरीजों का सफल पथरी ऑपरेशन कर उन्हें नई जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें देशभर में विशेष पहचान दिलाई। वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सदैव सहायता हेतु तत्पर रहते थे तथा अनेक मरीजों का निःशुल्क उपचार कर मानवता की मिसाल कायम की।

चिकित्सक होने के साथ-साथ डॉ. बंसल एक सक्रिय समाजसेवी और लोकप्रिय जननेता भी थे। वे दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा दो बार निगम पार्षद रहे। कांग्रेस संगठन में उनकी पहचान एक मजबूत स्तंभ, कर्मठ नेता और जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व के रूप में रही। उन्होंने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में हमेशा आमजन की आवाज़ उठाई और जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता दी।

उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक और चिकित्सा जगत की अनेक हस्तियों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए ह्न डॉ. भीमसेन बंसल को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जय प्रकाश अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मिर्ज़ा जावेद अली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रभारी डॉ. चंचल अग्रवाल, कूचा पंडित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय यादव, पूर्व निगम पार्षद कृष्ण मुरारी जाटव, पूर्व निगम पार्षद डॉ. आर.बी. सिंह तथा आशीष हरीचंद वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने भी स्वर्गीय डॉ. भीमसेन बंसल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ÷डॉ. बंसल का सामाजिक एवं मानवीय योगदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। उन्होंने अपने सेवा भाव, विनम्रता और समर्पण से समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।÷

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सुरेन्द्र कुमार बने उपाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

नई दिल्ली। (साहिल गौड़) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक ,सुरेन्द्र कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है। उनकी नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार लंबे समय से कांग्रेस संगठन एवं जनसेवा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक सरोकारों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें दी गई नई जिम्मेदारी से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अवसर पर किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी एवं रिपब्लिकन मजदूर संगठन की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार के नेतृत्व एवं अनुभव से दिल्ली कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और पार्टी संगठन को नई दिशा प्राप्त होगी। रिपब्लिकन मजदूर संगठन के महासचिव एवं पत्रकार विजय कुमार भारती ने कहा कि श्री सुरेन्द्र कुमार की नियुक्ति संगठनात्मक क्षमता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली में और अधिक सशक्त होकर जनता के मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया तथा श्री सुरेन्द्र कुमार के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

दिल्ली कांग्रेस को मिला मजबूत नेतृत्व-सुरेन्द्र कुमार बने उपाध्यक्ष

नई दिल्ली।(साहिल गौड़) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों में हर्ष की लहर है। उनकी नियुक्ति को संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार लंबे समय से जनसेवा, संगठन निर्माण एवं समाज के हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव, मिलनसार व्यक्तित्व और जमीनी पकड़ का लाभ दिल्ली कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके

नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। इस अवसर पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी तथा किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजय कुमार ने श्री सुरेन्द्र कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कांग्रेस संगठन के लिए सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री सुरेन्द्र कुमार अपने अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से संगठन को नई मजबूती प्रदान करेंगे तथा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे।कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों एवं पत्रकार जगत से जुड़े लोगों ने भी श्री सुरेन्द्र कुमार के उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की कामना की है।

टेलीग्राम पर वर्क फॉम होम का झांसा देकर 8 करोड़ ठगे, दिल्ली में अंतररायीय गिरोह के 14 जालसाज दबोचे

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में साइबर ठगी के एक अंतररायीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि यह गिरोह टेलीग्राम के जरिए संगठित तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहा था। डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 को गीता कालोनी स्थित एक होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां से अलग-अलग रायों के 12 आरोपितों को पकड़ा गया। पूछताछ और जांच के दौरान गिरोह के दो अन्य सदस्यों को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपित इंटरनेट मीडिया और नौकरी पोर्टल के जरिए लोगों को फर्जी नौकरी, घर से काम और अधिक वेतन का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम पर ले जाकर पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और अन्य बहानों से पैसे वसूले जाते थे। डीसीपी ने कहा कि गिरोह ठगी की रकम को छिपाने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। एक खाते से 40 से अधिक शिकायतें जुड़ी मिली हैं, जिनमें करीब 1.5 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जबकि एक एटीएम कार्ड तीन करोड़ रुपये की ठगी से संबंधित पाया गया। कुल मिलाकर आठ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान 18 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, तीन एटीएम कार्ड, चार चेकबुक और दो मुहर बरामद की गई हैं।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दाता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।

संपादक: विजय कुमार

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं।

Account Holder Name: ASHOKA EXPRESS
Bank Account No.
IFSC Code
UPI ID

दिल्ली कांग्रेस संगठन को मिली नई मजबूती- अनिल भारद्वाज बने महासचिव (संगठन)

नई दिल्ली। (आकाश शक्य)ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अनुशंसा तथा एआईसीसी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद की गई। नियुक्ति संबंधी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति दिल्ली पीसीसी प्रभारी एवं विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन द्वारा जारी की गई। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता, सौम्य व्यक्तित्व और मजबूत जनसंपर्क के लिए पहचाने जाने वाले अनिल भारद्वाज लंबे समय से कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। एक मृदुभाषी, मिलनसार और जन-जन में लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। दिल्ली कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है।

संगठनात्मक अनुभव, राजनीतिक समझ और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल उनकी विशेषता रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महासचिव (संगठन) के रूप में उनकी नियुक्ति से दिल्ली कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी के विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों ने अनिल भारद्वाज को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे संगठन हित में एक सकारात्मक कदम बताया है। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने अनिल भारद्वाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ÷अनिल भारद्वाज एक अनुभवी, कर्मठ और जमीनी नेता हैं। उनका सरल स्वभाव, संवाद क्षमता और कार्यकर्ताओं से आत्मीय जुड़ाव उन्हें विशेष बनाता है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस संगठन को नई दिशा और नई गति मिलेगी।÷ उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन को ऐसे अनुभवी और जनप्रिय नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मजबूत संवाद स्थापित कर सके। अनिल भारद्वाज निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और प्रभावशीलता के साथ निभाएंगे। दिल्ली कांग्रेस में इस नियुक्ति को आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठन विस्तार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शादी की तैयारियों के बीच घर खाली करने का नोटिस, यमुना बाजार के लोगों ने सरकार से लगाई गुहार

नई दिल्ली। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में इन दिनों लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल है. यमुना किनारे बसे इस इलाके में रहने वाले पंडा-पुजारी, नाविक और दूसरे परिवारों को सरकार की तरफ से घर खाली करने का नोटिस दिया गया है. 5 मई को जारी हुए इस नोटिस में लोगों से 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है. इस कार्रवाई के बाद यहां रहने वाले परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. सबसे यादा दर्द उस परिवार में देखा जा रहा है जहां 10 मई को बेटी की शादी होनी है. शादी की तैयारियों में जुटा परिवार अब घर बचाने की चिंता में डूब गया है. परिवार का कहना है कि शादी की खुशियां अचानक गम में बदल गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से यहीं रह रहे हैं. कुछ लोग पूजा-पाठ कर परिवार चला रहे हैं तो कुछ नाव चलाकर या मुंडन संस्कार कर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं. लोगों का कहना है कि अचानक से घर खाली करने का आदेश देना ठीक नहीं है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमारी कई पीढ़ियां यहां रही हैं. 15 दिनों में हम कहां जाएंगे? यही हमारा घर है, यही हमारा काम है और यही हमारी जिंदगी है. इलाके के लोगों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें हटाना चाहती है तो पहले रहने की दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए. लोगों ने मांग की है कि सरकार उन्हें सिर छुपाने के लिए छत दे, उसके बाद ही यहां से हटाने की बात करे. लोगों का कहना है कि वे इस मामले को लेकर एलजी और सरकार से बातचीत कर रहे हैं. अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. दरअसल, यमुना किनारे बसे इस इलाके में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है. जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है, सबसे पहले इन्हीं घरों में पानी भरता है. इसी वजह से सरकार इस इलाके को खाली कराना चाहती है ताकि बाढ़ के दौरान किसी तरह की जनहानि न हो. पिछले साल 2025 में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में करीब पांच फीट तक पानी भर गया था. उस समय लोगों को अपने घर छोड़कर राहत कैंपों में रहना पड़ा था. उस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इलाके का दौरा किया था और मदद का भरोसा दिया था. अब जिस तरह से लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है, उससे इलाके में नाराज़गी बढ़ती जा रही है. लोग खुद को बेघर होने के डर में जी रहे हैं. वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

इतना न उछलो बीजेपी वालों, अहंकार तो..., फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अपने साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है. अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. आप सांसद ने कहा है कि इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो? आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-÷ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में? लोकसभा की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ प्लेन में अभद्रता ये साबित करता है की बीजेपी का अहंकार चरम पर है. इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नही चला तो तुम क्या चीज हो? बेईमानी से चुनाव जीत कर इतना न उछ्लो बीजेपी वालों. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6ई-719 से दिल्ली यात्रा कर रही थीं. उनके अनुसार, वह विमान की सीट 1एफ पर बैठी थीं, तभी 4 से 6 लोगों का एक समूह विमान में सवार हुआ. टीएमसी सांसद का आरोप है कि ये लोग लगातार उन्हें घूरते रहे और बाद में विमान के पिछले हिस्से की ओर चले गए. उन्होंने कहा कि फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने के बाद, लेकिन विमान का दरवाजा खुलने से पहले, इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसके साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस घटना को उनकी सुरक्षा और निजी गरिमा का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसे जनता का गुस्सा÷ बताना गलत होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी हरकत थी, जिसका उद्देश्य उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना था.

भलस्वा डेरी में आधा दर्जन लोगों ने नाबालिग की चाकू घोंपकर की हत्या, पुरानी रंजिश का शक

बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी दिल्ली के भलस्वा डेरी क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन लोगों ने एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या का अभी सामने नहीं आया है, पुलिस फिलहाल इसे रंजिश का मामला मान कर जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से दो बाइक बरामद की हैं। मृतक के स्वजन का आरोप है कि हमलावरों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह सनसनीखेज वारदात कल शाम भलस्वा डेरी की तंदूर वाली गली में हुई। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम साढ़े सात बजे पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम, क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश आरंभ कर दी।

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में 48 घंटे में 482 अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी और एनसीआर में सक्रिय संगठित अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ अब तक का बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत 48 घंटे तक लगातार छापेमारी की. 5 मई सुबह 8 बजे से शुरू हुआ यह ऑपरेशन 7 मई सुबह 8 बजे तक चला. जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस ने 1014 ठिकानों पर रेड मारी और कुल 482 अपराधियों व गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, नकदी, नशीले पदार्थ, शराब और वाहन भी बरामद किए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बार ऑपरेशन में सिर्फ गैंगस्टरों को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया गया. इसमें शूटर्स, हथियार सप्लायर, फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले, फाइनेंसर, वाहन उपलब्ध कराने वाले सोशल मीडिया हैंडलर और ठिकाने देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई.

शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर सबसे बड़ा वार

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान समर्थित और ISI से जुड़े बताए जा रहे शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर कार्रवाई रही. पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को जोड़कर उन्हें देश

विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था. इन लोगों से सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई कराने और टारगेट किलिंग जैसे काम कराए जा रहे थे. स्पेशल सेल ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और गुजरात के आरोपी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करने का टास्क दिया गया था. कुछ आरोपी हथियार तस्करी में भी शामिल थे.

नंदू गैंग समेत कई बड़े गैंग्स पर शिकंजा

ऑपरेशन के दौरान कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए. इसके अलावा काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, टिल्लू, कौशल चौधरी, सद्दाम गौरी और अन्य गैंग्स के सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई. पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सबसे यादा 443 गिरफ्तारियां दूसरे छोटे-बड़े गैंग्स से जुड़े अपराधियों की हुई हैं.

भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद

इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 141 पिस्टल, 212 कारतूस, 79 चाकू, 24 वाहन ,करीब 19 लाख रुपये नकद, 19 किलो नशीला पदार्थ ,1234 शराब की बोतले बरामद किए है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जेलों और विदेशों में बैठे गैंग सरगनाओं के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 24 मई को

फरीदाबाद में 37, गुरुग्राम में 52 परीक्षा केंद्र मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने आगामी 24 मई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के सुचारू संचालन के लिए सम्बन्धित जिलों में पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के संचालन के लिए फरीदाबाद में 37 तथा गुरुग्राम में 52 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों तथा परीक्षा के निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन से संबंधित अन्य प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुगम परिवहन सुविधाएं और प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

'टीबी मुक्त हरियाणा' के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश - आरती सिंह राव

- 30 दिन की जांच में मिले 10,978 नए टीबी मरीज -राज्य सरकार टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध

चंडीगढ़ ।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि 'टीबी मुक्त हरियाणा' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। व्यापक जन-जागरूकता अभियान, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के चलते टीबी उन्मूलन को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 (विश्व टीबी दिवस) से शुरू किए गए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान (फेज-2) की 30 दिन की अंतरिम प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। इस अभियान के तहत अब तक 10,978 नए टीबी मरीजों की पहचान की जा चुकी है। यह सफलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों और सक्रिय केस खोज रणनीति के कारण संभव हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब राज्य की रणनीति केवल मरीजों के सामने आने का इंतजार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जाकर लक्षण रहित लोगों की भी जांच की जा रही है, ताकि छिपे हुए मामलों की समय रहते पहचान हो सके। आरती सिंह राव ने बताया कि हरियाणा में तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें दूरदराज क्षेत्रों में तुरंत जांच की सुविधा दे रही हैं। 'कफ अगेंस्ट टीबी' ऐप खांसी की आवाज का विश्लेषण कर संभावित मरीजों की पहचान करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की सफलता में जनभागीदारी की अहम भूमिका रही है। 65 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को 'चलती-फिरती लैब' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जांच संभव हो पाई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से टीबी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत टीबी जांच को सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ जोड़ा गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और एनीमिया की जांच भी शामिल है, ताकि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जियोस्पेशियल तकनीक के माध्यम से 2,111 संवेदनशील गांवों और वार्डों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उक्त अभियान के तहत 24 मार्च से 5 मई 2026 तक की गई गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में कुल 1620 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 938 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लगाए गए। इसी प्रकार 1,81,221 लोगों की स्क्रीनिंग की गई , 49,953 एनएएटी टेस्ट किए गए ,10,978 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई। उन्होंने आगे बताया कि उक्त अवधि में 335 नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए जबकि 8502 पोषण किट वितरित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और हर मरीज तक उपचार व सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को अब मिलेंगे 5000 रुपए - श्याम सिंह राणा

- कहा ,सहकारी मिल किसानों को उपलब्ध करवाएगी शुगरकेन हार्वेस्टर मशीन -टिश्यू कल्चर से गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को किया प्रोत्साहित

चंडीगढ़ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत जो किसान अब 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करेगा, उसको सरकार द्वारा 5 हज़ार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह प्रोत्साहन राशि 3 हज़ार रुपए प्रति एकड़ दी जा रही थी। श्री राणा ने यह जानकारी आज यहां विभागीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी है। उन्होंने कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को उचित दिशा -निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है ,इसलिए किसान को मज़बूत करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि पहले जो किसान 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना की रोपाई करता था तो सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन के तौर पर 3 हज़ार रुपए प्रति एकड़ दिए जाते थे , लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में यह राशि बढ़ाकर 5 हज़ार रूपये प्रति एकड़ करने की घोषणा की थी , इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार की ओर से इस संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को पोर्टल के माध्यम से 15 अक्तूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जाएगा , इसके बाद फरवरी 2027 के अंत तक भौतिक सत्यापन उपरांत संबंधित किसान को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि किसानों को एकल-आँख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है , पहले यह राशि 3 हजार रुपए प्रति एकड़ थी। श्री श्याम सिंह राणा यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की प्रत्येक सहकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगरकेन हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध करवाएगी ताकि किसानों की फसल कटाई पर लागत कम हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। इस विधि से तैयार हुई गन्ना की पौध को किसानों को मुफ़्त उपलब्ध करवाया जाएगा। करनाल सहकारी चीनी मिल द्वारा ये पौध तैयार की जाएगी। इस मिल से किसान अक्तूबर 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक पौध ले सकता है। श्री राणा ने कहा कि ये सभी पहल राज्य में कृषि को आधुनिक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इस अवसर बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार , निदेशक श्री राजनारायण कौशिक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निपुण वाटिका के माध्यम से लर्निंग को रूचिकर व आसान बनाया गया है- शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

चंडीगढ़ । हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चें मेधावी एवं प्रतिभाशाली हैं। अध्यापक वर्ग इन बच्चों को अपनी मेहनत से सही दिशा देने का कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निपुण वाटिका के माध्यम से लर्निंग कार्य को रूचिकर व आसान बना दिया है। विद्यार्थी खेल-खेल में रूचि लेकर सीख रहे हैं। मंत्री रोहतक जिला के गांव खरावड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्थापित की गई निपुण वाटिका का विधिवत उद्घाटन करने के उपरांत विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने जिला में शुरू की गई निपुण वाटिका व सुपर-40 की पहलों के लिए उपायुक्त सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारियों ने बच्चों के उवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा ने निपुण वाटिका का निरीक्षण करते हुए लर्निंग को रूचिकर और आसान बनाने के लिए किए गए प्रबंधों का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनकी पढ़ाई, गतिविधियों और रुचियों के बारे में जानकारी ली। निपुण वाटिका में समूह बनाना, पहाड़े, त्रिभुज, वर्ग, आयत, बढ़ता व घटता क्रम, ऊंचाई मापना, आकृतियां बनाना, सम व विषम संख्या को पहचानना, मात्राओं का ज्ञान, देश का मानचित्र, स्वर, व्यंजन, अक्षर ज्ञान आदि को डिजिटल रूप से पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चें रूचि लेकर इन गतिविधियों को सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता विकसित हो सके। उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि वे बच्चों को रचनात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करें ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी आत्मसात कर सकें। इस अवसर पर उपायुक्त सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता को बचपन से ही सही दिशा और उचित वातावरण देकर निखारा जाए। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेश में निपुण वाटिका और सुपर-40 जैसी अभिनव पहलें बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाना, लिखना सिखाना और उनकी झिझक को दूर करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

'प्रो-एक्टिव मॉडल' से बिना आवेदन घर बैठे मिल रहा योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफार्म तथा किसानों को जे फार्म व्हाटसएप पर भेजे जाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में आयोजित प्रैसवार्ता के दौरान प्रदेश के आमजन और किसानों को इन दो बड़ी सौगातों के अलावा 24 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2 हजार 115 करोड़ 41 लाख रुपये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी किए। इसके तहत 58 लाख 87 हजार 479 पात्र लाभार्थियों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने डीबीटी के माध्यम से जिन लाभार्थियों को राशि वितरित की गई है, उनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना की सातवीं किस्त,हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत जारी होने वाली सब्सिडी राशि, खरीफ फसल-2025 का मुआवजा, भावांतर भरपाई योजना की राशि के अलावा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन राशि शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना की सातवीं किस्त के तहत 9 लाख 76 हजार लाभार्थी बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर अब तक 7 किस्तों में 1 हजार 415 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज 18 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1 हजार 146 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि सीधे 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए 'प्रो-एक्टिव मॉडल' को अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण भी डीबीटी के माध्यम से किया गया है। सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के 64 हजार 923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि जारी की है। यह छात्रवृत्ति 2 लाख 50 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत पात्र विद्यार्थियों को जारी की गई है। इससे पहले छात्रवृत्ति राशि वितरित करने की प्रक्रिया विभिन्न विभागीय स्तर पर आधारित थी, जिसके कारण भुगतान में देरी व तकनीकी विसंगतियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए प्रदेश सरकार ने ओ.बी.सी., ई.बी.सी. और डी.एन.टी. योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ ऑन -बोर्ड किया है। इससे भुगतान की प्रक्रिया सरल हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 5 हजार 677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। साथ ही आज गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 11 लाख 23 हजार बहनों के बैंक खातों में फरवरी और मार्च माह की 38 करोड़ 54 लाख रुपये की सब्सिडी भी डाली है।

इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बारिश और जल भराव के कारण खराब हुई खरीफ फसल-2025 के लिए 1 लाख 50 हजार 583 किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की है। इसके तहत भिवानी जिले के 29 हजार 539 किसानों को 66 करोड़ 88 लाख रुपये तथा हिसार जिले के 25 हजार 812 किसानों को 64 करोड़ 40 लाख रुपये जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, किसानों को 6 हजार 272 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

पिछले साढ़े 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराब होने पर 9 हजार 888 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम भी दिये गये हैं। आज की राशि को मिलाकर प्रदेश में पिछले साढ़े 11 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 16 हजार 530 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में केवल 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी। यही नहीं, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी।

डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ते कदम, सीडीओ ने जनता से की सेल्फ इन्युमरेशन की अपील

देवरिया।

राष्ट्रीय जनगणना प्रविधि में आए क्रांतिकारी बदलावों और डिजिटल इंडिया के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों और आम जनता से सेल्फ इन्युमरेशन (स्व-गणना) प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया है। सीडीओ ने स्पष्ट किया है कि जनगणना की शुचिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा स्वयं का विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना एक सराहनीय और प्रभावी कदम है। प्रशासनिक स्तर पर दी गई जानकारी के अनुसार, नागरिक अब सरकार के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि इसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम रहती है। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने

त्रुटिहीन जनगणना के लिए तकनीक का सहारा ले रहा प्रशासन, पोर्टल के माध्यम से विवरण साझा करना हुआ आसान

व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस अभियान को गति प्रदान की है, ताकि देवरिया जनपद डिजिटल डेटा संकलन में अग्रणी भूमिका निभा सके। इस स्व-गणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े भविष्य में जिले के विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्धारण और संसाधनों के उचित आवंटन का मुख्य आधार बनेंगे। उल्लेखनीय है कि स्व-गणना की यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य देश की जनगणना को पेपरलेस और अत्याधुनिक बनाना है। प्रशासन का मानना है कि यदि जनपद के निवासी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले सत्यापन कार्य में भी सुगमता होगी। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और दिए गए लिंक का उपयोग कर जल्द से जल्द अपनी प्रविष्टि दर्ज करें।

गोरखपुर के धुरियापार में इसी माह होगा अंबुजा सीमेंट प्लांट का शिलान्यास, सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल

गोरखपुर। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के अंतर्गत विकसित हो रहे धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने की संभावना है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और 20 से 30 मई के बीच कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। अदाणी की ओर से प्रस्तावित योजना के अनुसार करीब 1400 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली यह फैक्ट्री धुरियापार चीनी मिल परिसर के पास लगभग 46 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। फैक्ट्री शुरू होने के बाद करीब एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि परिवहन, निर्माण, होटल, व्यापार और अन्य सहायक गतिविधियों में हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र को हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद यहां उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। अदाणी समूह की यह परियोजना इस क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल मानी जा रही है। फैक्ट्री अंबुजा सीमेंट ब्रांड के तहत संचालित होगी।कंपनी ने ऐसी जमीन का चयन किया है, जो प्रस्तावित सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन के बेहद करीब है। इससे कच्चे माल की ढुलाई और तैयार उत्पाद के परिवहन में आसानी होगी। बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी के कारण धुरियापार क्षेत्र निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अदाणी समूह के अलावा कई अन्य बड़े औद्योगिक घराने भी निवेश की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस कंयूमर प्रोडक्ट्स

यहां कैंपा कोला का बाटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जबकि श्रेयस ग्रुप डिस्टिलरी और एथेनाल प्लांट लगाने की प्रक्रिया में है। वहीं, जेके सीमेंट ने भी यहां अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन की मांग की है। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अदाणी समूह के अलावा कई अन्य बड़े औद्योगिक घराने भी निवेश की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस कंयूमर प्रोडक्ट्स यहां कैंपा कोला का बाटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जबकि श्रेयस ग्रुप डिस्टिलरी और एथेनाल प्लांट लगाने की प्रक्रिया में है। वहीं, जेके सीमेंट ने भी यहां अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन की मांग की है। औद्योगिक परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के चलते धुरियापार को अब 'पूर्वांचल का नोएडा' कहा जाने लगा है। लिंक एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क और औद्योगिक कारिडोर की बेहतर कनेक्टिविटी आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक केंद्र बना सकती है।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक पर बनेगा होल्डिंग एरिया, एक हजार यात्रियों के ठहरने की होगी व्यवस्था

गोरखपुर। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक पर होल्डिंग एरिया (यात्रियों के ठहरने का स्थान) बनेगा। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को उचस्तरीय सुविधाएं मिलेगी। ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिलने के साथ प्लेटफार्मों तक पहुंचने की भी व्यवस्था रहेगी। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन केंद्र होंगे। होली और छठ पर्व आदि के समय यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है। जिसमें करीब एक हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। रेलवे बोर्ड की पहल पर लखनऊ मंडल प्रशासन ने होल्डिंग एरिया के लिए भूमि चिह्नित कर ली है। प्रस्ताव तैयार कर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामी सर्विस (राइट्स) के पास भेज दिया है। जल्द ही राइट्स द्वारा सर्वे किया जाएगा। राइट्स की मंजूरी के बाद निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों का कहना है कि होल्डिंग एरिया के लिए गेट नंबर एक के पास पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (पीआरकेएस) कार्यालय व खाली परिसर में भूमि चिह्नित की गई है। होल्डिंग एरिया निर्माण के लिए पीआरकेएस का कार्यालय टूट सकता है। कार्यालय को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कार्यालय को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए रेलवे प्रशासन स्तर पर मंथन शुरू है। गेट नंबर एक पर सड़क के किनारे होल्डिंग एरिया बनने से यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, खाली भूमि का उपयोग भी हो सकेगा।फिलहाल, लगभग 500 करोड़ रुपये से गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास शुरू हो चुका है। मई 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। 07 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। पुनर्विकास के बाद गोरखपुर जंक्शन पर ही बजट होटल, कामर्शियल कांप्लेक्स और रेस्तरां की सुविधा मिल जाएगी। यात्री मल्टीप्लेक्स में मूवी का आनंद उठा सकेंगे। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले लोग कार पार्क के करने के साथ मनमाफिक खरीददारी भी कर सकेंगे। परिसर में ही मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। रेलवे और बस स्टेशन को जोड़ने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा। जंक्शन पर और दो नए प्लेटफार्म भी बनेंगे। नए प्लेटफार्म साउथ-वेस्ट बिल्डिंग और प्लेटफार्म एक के बीच प्लेटफार्म नंबर टू ए के सीध में बनेंगे। जंक्शन पर कुल 12 प्लेटफार्म हो जाएंगे।

गोरखपुर में जनगणना स्वगणना के दौरान जटिल सवालों से नागरिक उलझे, पहले दिन 1300 से अधिक ने की गणना

गोरखपुर। महानगर के तारामंडल क्षेत्र के एक व्यापारी ने गुरुवार की दोपहर उत्साहित होकर स्वगणना के लिए जनगणना पोर्टल खोला। सवालों के जवाब देना शुरू ही किया था कि अटक गए। घर की फर्श की मुख्य सामग्री (टाइल्स, सीमेंट, लकड़ी आदि) से जुड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए दिमाग पर जोर डाला तो पाया कि आगे के दो कमरों, किचन और टायलेट में टाइल्स और बाकी में साधारण फर्श है। समझ नहीं पाए कि जानकारी क्या दर्ज करें। गलत जानकारी न दर्ज हो इसलिए सही जानकारी प्राप्त करने या फिर प्रगणक आने पर ही जानकारी दर्ज करने की मंशा के साथ लैपटाप बंद कर दिया। इसी तरह शिक्षा विभाग में तैनात एमएमयूटी क्षेत्र की एक कालोनी के कर्मचारी जब घर में एलपीजी है पीएनजी या सीएनजी से जुड़े सवाल पर पहुंचे तो उलझ गए। उनके घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों का कनेक्शन है। रसोई गैस का संकट गहराने के समय उन्हें जानकारी हुई थी कि पीएनजी वाले एलपीजी के लिए नहीं बुकिंग कर सकते। यह सोचकर बीच में ही स्वगणना की प्रक्रिया बंद कर दी। यह तो बानगी है। जनगणना के सवालों में उलझकर कई लोग स्वगणना नहीं कर सकें। वहीं पहले ही दिन 1300 से अधिक लोग स्वगणना करने में सफल रहे। जनगणना-2027 के तहत गुरुवार से स्वगणना का शुभारंभ हो गया। जनगणना के नोडल अधिकारी व एडीएम (फाइनेंस) विनीत सिंह के अनुसार पहले दिन गोरखपुर से 1319 से अधिक लोगों ने जनगणना पोर्टल पर आनलाइन खुद अपने घर व परिवार की जानकारी दर्ज की। इनमें राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। स्वगणना को लेकर मंडल में सबसे अधिक गोरखपुर के लोगों ने ही जागरूकता दिखाई है। शासन स्तर से शाम पांच बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देवरिया में 700, महराजगंज में 600 और कुशीनगर से सबसे कम 340 लोगों ने स्वगणना की।

बाढ़ प्रबंधन को रोहिन नदी के तटबंधों पर बन रहे दो पंपिंग स्टेशन

गोरखपुर।

बाढ़ प्रबंधन को लेकर योगी सरकार की तरफ से किए गए ठोस उपायों की श्रृंखला में दो और महत्वपूर्ण कार्य जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड ने उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को बाढ़ से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्ययोजना बनाकर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत रोहिन नदी के किनारे बसे गांवों और नव शहरी क्षेत्रों को मानसून के मौसम में जलमग्न होने से बचाने के लिए दो स्थलों पर पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मानसून के समय काफी संवेदनशील हो जाने वाली रोहिन नदी पर बने तटबंधों को सुदृढ़ करने के साथ ही तटबंध के किनारे के क्षेत्रों में जल प्लावन की समस्या से निजात दिलाने के लिए मछलीगांव-अलगटपुर तटबंध और मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंध पर दो पंपिंग स्टेशन अगले वर्ष जून माह तक बनाकर तैयार हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हर साल मानसून के दौरान रोहिन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों के किनारे बसे मोहल्लों और खेतों में पानी जमा हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बाधित होने के कारण

यह पानी हफ्तों तक नहीं निकल पाता। इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। ड्रेनेज खंड के अधिशासी अभियंता आनंद गौतम बताते हैं कि एक पंपिंग स्टेशन रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मछलीगांव-अलगटपुर तटबंध के किमी 18.200 पर कलान नाले पर कल्याणपुर के पास बनाया जा रहा है। करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले पंपिंग स्टेशन में 40 क्यूसेक क्षमता के सात पंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहां एक स्टैंडबाई पंप सहित 20 क्यूसेक क्षमता के तीन पंप भी होंगे। पंपों के निर्बाध संचालन के लिए 750 केवीए के चार डीजल जेनसेट और 62.5 केवीए का एक जेनसेट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 35 प्रतिशत से अधिक कार्य कराया जा चुका है। दूसरा पंपिंग स्टेशन रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंध के किमी 10 पर ग्राम सिरिया के पास 57 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है। करीब 40 प्रतिशत भौतिक प्रगति वाली इस परियोजना में भी 40 क्यूसेक क्षमता के सात पंप लगाए जाएंगे। साथ ही

सीएम योगी के निर्देश पर जिले के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को बाढ़ से बचाने के लिए तैयार की गई है कार्ययोजना करीब 55 करोड़ और 57 करोड़ रुपये की लागत से दो पंपिंग स्टेशन बनवा रहा है सिंचाई विभाग दोनों पंपिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे 40 क्यूसेक की क्षमता के सात-सात पंप

एक स्टैंडबाई पंप सहित 20 क्यूसेक क्षमता के तीन पंप भी होंगे। पंपों के संचालन के लिए 750 केवीए के चार डीजल जेनसेट और 62.5 केवीए के एक जेनसेट की व्यवस्था होगी। ड्रेनेज खंड के अधिशासी आनंद गौतम बताते हैं कि रोहिन नदी पर बनने वाले ये स्टेशन न केवल ग्रामीण इलाकों की फसलों को डूबने से बचाएंगे, बल्कि शहरी सीमा से सटे उन इलाकों को भी राहत देंगे जहां नदी के बैकवॉटर के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं।

एमजीयूजी का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षण व्यवस्था उत्कृष्ट - डॉ. शशिबाला

डीआरडीओ में जीवन विज्ञान की पूर्व महानिदेशक ने एमजीयूजी का किया भ्रमण, समीक्षा बैठक में हुई शामिल

गोरखपुर।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) मुख्यालय नई दिल्ली में जीवन विज्ञान की पूर्व महानिदेशक तथा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की पूर्व निदेशक डॉ. शशिबाला सिंह ने कहा है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षण व्यवस्था उत्कृष्ट है। यह विश्वविद्यालय समय के अनुकूल शोध और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है। डॉ. शशिबाला सिंह एमजीयूजी के दो दिवसीय भ्रमण पर आई थीं। सात मई, गुरुवार को उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न शैक्षणिक एवं अधोसंरचनात्मक

संसाधनों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक भवनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालय सुविधाओं तथा पंचकर्म केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद वह शुक्रवार, आठ मई को कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आहुत समीक्षा बैठक में शामिल हुईं। इस बैठक में विभिन्न संकायों की प्रगति, गतिविधियों, विशिष्टताओं एवं सामर्थ्य की समीक्षा की गई। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कृषि तथा वाणिय संकायों के अधिष्ठाताओं, प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए भावी विकास योजनाओं एवं अंतर्विषयी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर डॉ. शशिबाला सिंह ने एमजीयूजी के कुलाधिपति, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विकसित विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संस्थागत सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियां सही दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने शोध एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु रणनीतिक पहलों, उद्योग-अकादमिक सहभागिता तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल-आधारित एवं रोजगारोन्मुखी नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

माननीय प्रधानमंत्री-भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती रेखा गुप्ता जी

पूर्व केजरीवाल सरकार का कमाऊ पूत

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के

ई.ई, ए.ई, कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा 11 वर्षो से विकास एवं निर्माण कार्य में बेहद घटिया निर्माण सामग्री व फर्जी बिल लगाकर।

करोड़ो के घोटाले व भष्टाचार की जांच

श्रीमान निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से कराई जाएं।

छठ घाटो में टेन्ट, पानी टैंकर, बड़े नालो की साफ-सफाई, बॉउन्ड्रीवाल के

फर्जी बिल लगाकरकिए गए करोड़ो के घोटाले और हरे-भरे पेड़ो को काटकर खुलेआम बेचा जा रहा है।

I&FC के श्री अशोक कुमार-(FC-III), ए.सुरेन कुमार (पीएनडी), अनुराग जैन (CD-I), विवेक चौहान (CD-II), शोभित जैन (CD-III), सोमनाथ कश्यप (CD-IV), बी.बी.नागपाल (CD-V), जे.नरेन्द्र सागर (CD-VI) प्रदीप नैक (CD-VII), पुनित डुडेजा (CD-IX), प्रशांत मिश्रा (CD-X), विवेक चौहान (CD-XI), गगन गौड़ (CD-XII), सुधीर कुमार आर्य (S.W-1 & CD-XIII), शिव कुमार (CD-XIV), जे.नरेन्द्र सागर (CD-XV) एई, जे.ई ने ठेकेदारों की मिलीभगत से दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री और फर्जी बिल बनाकर कर रहे है अपना समाजवाद दूर!

भ्रष्टाचारियों व कमिशन खोरो का अड्डा बना

श्री सुधीर कुमार आर्य, ई.ई, सतर्कता कार्यालय: बसई दारापुर?

निवेदक: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा (विज्ञापन)